भारत सरकार
सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय

राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 159
03.02.2025 को उत्तर देने के लिए

आदिवासी परिवारों की औसत आय

159. श्रीमती फूलो देवी नेतमः

क्या सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) देश में ग्रामीण और शहरी महिलाओं और पुरुषों की औसत आय कितनी है, गत तीन वर्षों के दौरान छत्तीसगढ़ सहित राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ख) छत्तीसगढ़ के बस्तर संभाग के आदिवासी परिवारों में महिलाओं और पुरुषों की औसत आय कितनी है;

(ग) आदिवासी परिवारों की औसत आय बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किए जा रहे हैं; और

(घ) उक्त उपायों से गत तीन वर्षों में बढी हुई औसत आय सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), योजना मंत्रालय राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) तथा कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय राज्य मंत्री [राव इंद्रजीत सिंह]

(क) से (घ): सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (सां. और कार्य. कार्य. मंत्रा.) के अंतर्गत राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ) का सर्वेक्षण स्कंध अखिल भारतीय आधार पर विभिन्न सामाजिक-आर्थिक विषयों पर बड़े पैमाने पर प्रतिदर्श सर्वेक्षण आयोजित करने के लिए उत्तरदायी है। तथापि, इन सर्वेक्षणों में देश में ग्रामीण और शहरी महिलाओं और पुरुषों की औसत आय का अनुमान नहीं लगाया जाता है।

सरकार देश में जनजातियों के कल्याण और विकास के लिए विभिन्न योजनाएं/कार्यक्रम कार्यान्वित कर रही है। जनजातीय कार्य मंत्रालय (एमटीए) अनुसूचित जनजातियों के विकास के लिए समग्र नीति नियोजन और कार्यक्रमों के समन्वय हेतु नोडल मंत्रालय है। यह देश भर के सभी जनजातीय लोगों और जनजातीय आबादी वाले सभी क्षेत्रों को शामिल करता है। जनजातीय कार्य मंत्रालय के अलावा, 41 मंत्रालय/विभाग शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, सिंचाई, सड़क, आवास, रोजगार सृजन, कौशल विकास आदि से संबंधित परियोजनाओं के लिए जनजातीय विकास हेतु हर वर्ष अपने कुल योजना बजट का कुछ प्रतिशत आवंटित कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त, जनजातीय कार्य मंत्रालय ने अपनी दो एजेंसियों नामतः भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन

विकास संघ (ट्राइफेड) और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास निगम (एनएसटीएफडीसी) के माध्यम से जनजातीय समुदायों द्वारा संचालित की जा रही आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है और बदले में उनके आर्थिक विकास को प्रभावित किया है।

जनजातीय कार्य मंत्रालय, ट्राइफेड के माध्यम से 'प्रधानमंत्री जनजातीय विकास मिशन (पीएमजेवीएम)' योजना को लागू कर रहा है, जिसका उद्देश्य जनजातीय उद्यमिता पहलों को सुदृढ़ करना और प्राकृतिक संसाधनों, कृषि/लघु वन उपज (एमएफपी)/गैर-कृषि उपज के अधिक कुशल, न्यायसंगत, स्व-प्रबंधित, इष्टतम उपयोग को बढ़ावा देकर आजीविका के अवसरों को सुविधाजनक बनाना है।

इस योजना के अंतर्गत , प्रत्येक वन धन विकास केंद्र (वीडीवीके) की स्थापना के लिए राज्य सरकारों को 15.00 लाख रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है, जो एमएफपी/गैर-एमएफपी के मूल्य संवर्धन गतिविधियों के केंद्र हैं। ट्राइफेड जनजातीय कारीगरों/आपूर्तिकर्ताओं को ऑनलाइन और ऑफलाइन मंचों के माध्यम से धातु शिल्प, वस्त्र, आभूषण, चित्रकारी, बेंत और बांस, टेराकोटा और मिट्टी के बर्तन, जैविक और प्राकृतिक खाद्य उत्पाद आदि जैसे विभिन्न श्रेणियों के जनजातीय उत्पादों के विपणन के लिए बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेज भी प्रदान करता है।

इसके अतिरिक्त, ट्राइफेड जनजातीय कारीगरों को अपने उत्पादों को प्रदर्शित करने तथा उन्हें संभावित खरीदारों से जोड़ने के लिए मंच प्रदान करने हेतु उत्सवों, मेलों आदि का आयोजन करता है तथा उनमें भाग लेता है, जिससे उन्हें अपनी उद्यमशीलता गतिविधियों तथा कमाई की क्षमता को बढ़ाने का अवसर मिलता है।

****